



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 279]
No. 279]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 24, 1983/आषाढ़ 3, 1905

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 24, 1983/ASADHA 3, 1905

इस भाग में भिन्न-वृष्टि संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

गृह मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जून, 1983

क्र. आ. 473(अ) :—राष्ट्रपति आदेश किया गया
निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिये
प्रकाशित किया जाता है :—

अधिसूचना

अधिसूचना सं. 473(अ) :—राष्ट्रपति को, पाँचवरी
संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक से एक रिपोर्ट प्राप्त हुई है और
उस रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् मेरा यह समाधान
हो गया है कि इसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें पाँच-
वरी संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन
अधिनियम 1963 (1963 का 20) क (जिस इसमें इसके
पश्चात् अधिनियम का संशोधन है), उपबन्धों की अनुसूची
नहीं चलाया जा सकता है,

अधिसूचना सं. 473(अ) :—राष्ट्रपति को, पाँचवरी
संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक से एक रिपोर्ट प्राप्त हुई है और
उस रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् मेरा यह समाधान
हो गया है कि इसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें पाँच-
वरी संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन
अधिनियम 1963 (1963 का 20) क (जिस इसमें इसके
पश्चात् अधिनियम का संशोधन है), उपबन्धों की अनुसूची
नहीं चलाया जा सकता है,

अन्य अधिनियमों के प्रयोग करने वाले देशों में इस आदेश द्वारा—
(क) अधिनियमों के निम्नलिखित उपबन्धों का प्रवर्तन
उक्त पाँचवरी संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में
इस आदेश की तारीख से छह मास की अवधि
के लिये सीमित करने का कार्य होगा अर्थात् :—

धारा 8 की उपधारा (1) और उपधारा (2) का खंड (क);
धारा 15 के उपधारा (1) (ख) और (4) उपधारा (2) के खंड
(ख) और (ग) और उस उपधारा का पहला
पैरा परन्तु; और उपधारा (5) का उतना भाग
जो उपधारा के अंतर्गत और धर्मा से संबंधित

धारा 8 से 12 (जिनमें ये दोनों धाराएँ सम्मिलित हैं);

धारा 15 से 17 (जिनमें ये दोनों धाराएँ सम्मिलित हैं);

धारा 22;

धारा 27 की उपधारा (1) का उक्त भाग जिसके लिये
राष्ट्रपति के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होती है और
उसी धारा की उपधारा (3) के खंड (ग) का उतना

भाग जो उपाध्यक्ष के वेतन और भत्तों से संबंधित है ;

धारा 30 की उपधारा (1) का उतना भाग जिसके लिये राष्ट्रपति के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होती है ;
धारा 33, धारा 34 की उपधारा (2) और धारा 36 ;
धारा 44 और 45 ;

धारा 46 की उपधारा (1) और उपधारा (2) का निम्नलिखित उपबंध अर्थात् :—

“चाहे अपने मंत्रियों की सलाह पर या अन्यथा की गई हो” और

धारा 50 का उतना भाग जो मंत्रि परिषद् से संबंधित है ;
और

(ख) निम्नलिखित आनुवंशिक और पारिणामिक उपबंध करता हूँ जो मुझे पूर्वोक्त अवधि के दौरान संविधान के अनुच्छेद 239 के उपबंधों के अनुसार पॉन्डिचेरी संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन करने के लिये आवश्यक और समीचीन प्रतीत होते हैं, अर्थात्:—

- (i) उक्त संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा का विघटन किया जाता है ;
- (ii) अधिनियम की धारा 45 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किये गये मुख्य मंत्री और अन्य मंत्री उस हैसियत से अपने पद पर नहीं रहेंगे ,
- (iii) जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो उक्त संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में, अधिनियम की धारा 6, 23, 27, 28, 30 और 49 में प्रशासक के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जायेगा कि वह राष्ट्रपति के प्रति निर्देश है और धारा 23, 27 से 31 (जिनमें ये दोनों धारा सम्मिलित हैं), 48 और 49 में किसी संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा के प्रति निर्देश का, चाहे वह किन्हीं भी शब्दों में हो, जहाँ तक उसका संबंध उसके कृत्यों और शक्तियों से है, यह अर्थ लगाया जायेगा कि वह संसद के प्रति निर्देश है।

नई दिल्ली
तारीख 24 जून, 1983

जैल सिंह,
भारत का राष्ट्रपति

[फा० सं० यू-11012/1/83-यू०टी०एल०]

एम० वरदान, अपर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th June, 1983

S.O. 473(E).—The following Order, made by the President is published for general information :—

ORDER

Whereas I, Zail Sings, President of India, have received a report from the Administrator of the Union territory of Pondicherry and after considering the report, I am satisfied, that a situation has arisen in which the administration of the Union territory of Pondicherry cannot be carried on in accordance with the provisions of the Government of Union Territories Act, 1963 (20 of 1963) (hereinafter referred to as “the Act”);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 51 of the Act and of all other powers enabling me in that behalf, I hereby—

(a) suspend, for a period of six months from the date of this order, in relation to the said Union territory of Pondicherry, the operation of the following provisions of the Act, namely :—

Sub-section (1) and clause (a) of sub-section (2) of section 6 ;

in section 7, sub-sections (1), (3) and (4), clauses (b) and (c) of sub-section (2) and the first proviso to that sub-section, and so much of sub-section (5) as relates to the salaries and allowances of the Deputy Speaker ;

sections 8 to 12 (both inclusive), sections 15 to 17 (both inclusive) ;

section 22 ;

so much of the sub-section (1) of section 27 as requires the previous approval of the President and so much of clause (c) of sub-section (3) of the same section as relates to the salaries and allowances of the Deputy Speaker ;

so much of sub-section (1) of section 30 as requires the previous approval of the President ;

Section 33, sub-section (2) of section 34 and section 36 ;
sections 44 and 45 ;

sub-section (1), and the following provision, namely,

“whether taken on the advice of his Ministers or otherwise” in sub-section (2) of section 46; and

so much of section 50 as relates to the Council of Ministers ; and

(b) make the following incidental and consequential provisions which appear to me to be necessary and expedient for administering the Union territory of Pondicherry in accordance with the provisions of article 239 of the Constitution during the aforesaid period, namely :—

(i) the Legislative Assembly of the said Union territory is hereby dissolved ;

- (ii) the Chief Minister and the other Ministers appointed under sub-section (1) of section 45 of the Act shall cease to hold office as such ;
- (iii) in relation to the said Union territory, unless the context otherwise requires, any reference in sections 6, 23, 27, 28, 30 and 49 of the Act to the Administrator shall be construed as a reference to the President and any reference in sections 23, 27 to 31 (both inclusive), 48 and 49 to the Legislative Assembly of a Union territory by whatever form of words shall, in so far as it relates to the functions and

powers thereof, be construed as a reference to Parliament.

New Delhi,
the 24th June, 1983.

ZAIL SINGH,
PRESIDENT OF INDIA
[No. U-11012/1/83-UTL]
S. VARADAN, Addl. Secy.

of the Court. The Court of the Office of the Attorney General shall have jurisdiction over the Court of the Office of the Attorney General.

(iii) in relation to the Court of the Office of the Attorney General, the Court of the Office of the Attorney General shall have jurisdiction over the Court of the Office of the Attorney General.

Page 11 of 11

Page 11 of 11

Page 11 of 11

Page 11 of 11

Page 11 of 11

Page 11 of 11

Page 11 of 11

Page 11 of 11

Page 11 of 11

Page 11 of 11

Page 11 of 11

Page 11 of 11

Page 11 of 11

Page 11 of 11

Page 11 of 11

Page 11 of 11

Page 11 of 11

Page 11 of 11

Page 11 of 11

Page 11 of 11

Page 11 of 11

Page 11 of 11

Page 11 of 11

Page 11 of 11

Page 11 of 11

Page 11 of 11

Page 11 of 11

Page 11 of 11

Page 11 of 11

Page 11 of 11

Page 11 of 11

Page 11 of 11

Page 11 of 11

Page 11 of 11

Page 11 of 11

Page 11 of 11

Page 11 of 11

Page 11 of 11

Page 11 of 11

Page 11 of 11

Page 11 of 11

Page 11 of 11

Page 11 of 11

Page 11 of 11

Page 11 of 11

Page 11 of 11

Page 11 of 11

Page 11 of 11

Page 11 of 11

Page 11 of 11

Page 11 of 11

Page 11 of 11

Page 11 of 11

Page 11 of 11

Page 11 of 11